पुस्तक समीक्षा

शिक्षा जो स्वर साध सके

विजय कुमार यादव*

पुस्तक का नाम	—	*शिक्षा जो स्वर साध सके*
लेखक	—	आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल
संपादक	—	ऋषभ कुमार मिश्र
प्रकाशक	—	वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
प्रकाशन वर्ष	—	2021
मूल्य	—	₹145

शिक्षा संबंधी नीति में राष्ट्र और समाज विशेष का इतिहास एवं संस्कृति बोध प्रतिबिंबित होता है। इसके सापेक्ष शिक्षा नीतियाँ समाज के भविष्य की रूपरेखा को तय करने वाला दस्तावेज होती हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत पुस्तक 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' की विवेचना करती है। यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण कृति है। यह भारतीय शिक्षा के इतिहास से परिचित कराते हुए उसकी वर्तमान चुनौतियों के मूलभूत कारणों का विश्लेषण करती है। इसके उपरांत 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का सम्यक विवेचन करते हुए उसके क्रियात्मक सूत्रों को भी प्रस्तुत करती है।

शिक्षा का इतिहास बोध

शिक्षा जो स्वर साध सके पुस्तक के प्रथम अध्याय में आचार्य शुक्ल ने भारतीय संदर्भों में शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रेखांकित किया है कि शिक्षा का लक्ष्य लोक कल्याणकारी समाज की निर्मिति है, जिसमें सामंजस्य रखने वाली जीवन प्रणाली परिलक्षित होती है, इसके बिना शिक्षा प्रशिक्षण मात्र है। तदुपरांत उन्होंने बताया है कि प्रारंभ में शिक्षा को अच्छा नागरिक एवं अच्छा मनुष्य बनाने वाली प्रक्रिया के संदर्भ में देखा गया है। किंतु शिक्षा का लक्ष्य इतना सीमित नहीं है। मनुष्य का निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसका घटक स्वयं मनुष्य है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि अच्छी शिक्षा के दो घटक हैं— प्रथम, शिक्षा जीविका के लिए तैयार करती है और द्वितीय, शिक्षा जीवों का उद्धार करती है अर्थात शिक्षा सामाजिक एवं भौतिक सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति का उपक्रम है। इस अध्याय में उल्लिखित है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से शिक्षा

**शोधार्थी,* शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

को उत्पादकता बढ़ाने का संसाधन समझा गया, जिसके लिए शिक्षा को अनुशासित नागरिक बनाने की प्रक्रिया के रूप में समझा गया, किंतु इसे उच्चतर मूल्य विकसित करने के लिए प्रश्न खड़ा करने के रूप में देखने की आवश्यकता थी। इस तर्क के समर्थन में आचार्य शुक्ल उपनिषदों एवं अन्य भारतीय साहित्यों का संदर्भ लेते हैं और बताते हैं कि व्यक्ति एवं समाज को नित्य और समग्र रूप में सोचना पड़ेगा।

'शिक्षा का रमणीक वृक्ष— एक सिंहावलोकन' नामक अध्याय 2 में लेखक ने शिक्षा पर उपनिवेशवाद के प्रभाव की व्याख्या की है। इस अध्याय में स्थापित किया गया है कि प्रारंभ में भारत में शिक्षा की व्यवस्था स्वायत्त, स्वतंत्र और राज्य की व्यवस्था के समानांतर थी तथा उसमें हस्तक्षेप का अधिकार राज्य को नहीं था। 1835 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, उसने शिक्षा को एक प्रकार से राज्य चलाने का साधन बना दिया। आगे चलकर शिक्षा का बाजार की परिधि में क्रय-विक्रय होने लगा। इस तरह से यह अध्याय समग्रता में उपनिवेशवाद जन्य परिवर्तनों को पाठकों के सामने रखता है।

'भारतीय लोक चिंतक और शिक्षा' में भारतीय लोक चिंतकों द्वारा परिकल्पित शिक्षा की संकल्पना को अध्याय 3 में प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय पाठकों को परिचित कराता है कि भारतीय लोक चिंतकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पूर्णता की खोज, पूर्णता का अनुभव, पूर्णता की अभिव्यक्ति, पूर्णता का आकारीकरण है। इस तरह से शिक्षा समग्र विकास का आधार है। हमने इस वृहद दृष्टि की उपेक्षा की और मनुष्य को मात्र उत्पादक एवं मशीन बनाने वाली औपनिवेशिक शिक्षा को स्वीकार कर लिया।

भारतीयता का पुनरुत्थान

अध्याय 4 से अध्याय 8 में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की आधारभूत मान्यताओं की व्याख्या की गई है। इसमें शिक्षा के लक्ष्य एवं नए प्रस्तावित परिवर्तनों की प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया है। ये अध्याय भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनरुत्थान पर बल देते हैं। अध्याय 4 में लेखक ने चर्चा की है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं को शिक्षा का आधार मानती है तथा भारतीय चिंतकों की दृष्टियों को अंगीकार करते हुए इक्कीसवीं सदी के भारत को सशक्त बनाने की ओर अग्रसर है।

'शिक्षा का साध्य मनुष्य' नामक अध्याय 5 में उल्लिखित किया गया है कि स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा संबंधी विभिन्न दस्तावेजों एवं शिक्षा नीतियों, जैसे— शिक्षा आयोग, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968,* काका कालेलकर कमेटी, नरेंद्र देव कमेटी इत्यादि में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन न होने के कारण आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमियाँ उजागर हो रही हैं। लेखक ने प्रकाश डाला है कि विभिन्न कारणों से हमारी व्यवस्थाएँ कहने को तो भारतीय थीं, परंतु उनके लक्ष्य भारतीयता से भटके हुए थे। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* मानव संसाधन मॉडल को खारिज करती है। यह नीति भारतीय जन, भारतीय समाज तथा भारत राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है।

संस्कृत बोध एवं भारत बोध पर भारतीय शिक्षा नीति की प्रासंगिकता और उसमें निहित तत्वों की विवेचना अध्याय 6 और अध्याय 7 में की गई है। लेखक का मत है कि, *शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, 1966* और *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968* स्वतंत्र भारत में शिक्षा में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल थी, जिसमें शिक्षा को मूल्यपरक बनाने और भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर बल दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इस सांस्कृतिक चेतना को हम भारतीय शिक्षा का आधार नहीं बना सके। परिणामस्वरूप शिक्षा मनुष्य निर्माण के बजाय नागरिक निर्माण की भूमिका में आ गई। लेखक का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र नागरिक निर्माण नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के अभ्यंतर का अभ्युदय होना चाहिए, जिसे गांधी, विवेकानंद और विनोबा आदि ने शिक्षा के लक्ष्य के रूप में प्रतिपादित किया था। लेखक *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को इन भटकावों से अलग भारतीय हित चिंतकों की दृष्टि को साकार करने वाली शिक्षा नीति के रूप में देखते हैं। लेखक इस नीति का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि यह नीति भारतीय परंपरा के अनुरूप शिक्षा को शाश्वत मूल्यों से पोषित, जिज्ञासु मस्तिष्क के विकास का माध्यम बनाना चाहती है। इसके लिए शिक्षा नीति परीक्षा प्रणाली व शिक्षण के किसी एकमात्र साधन की बात नहीं करती है। इसमें उस प्रत्येक प्रणाली के तत्व विद्यमान हैं जो शिक्षार्थी को विद्यालयी स्तर और विषय अनुरूप सीखने का अवसर देती है। यह तारतम्यता पूर्व प्राथमिक स्तर से शोध तक विद्यमान है।

'परंपरा और आधुनिकता की बहस' नामक अध्याय 8 में लेखक विश्लेषित करते हैं कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यह नीति घोषित करती है कि हमारी पारंपरिक शिक्षा अपनी विषय-वस्तु और पद्धति दोनों दृष्टिकोण से पूर्णतया प्रासंगिक है। लेखक कहते हैं कि भारतीय परंपरा में निहित सिद्धांत, 'प्रत्येक पढ़ेगा और प्रत्येक बढ़ेगा' को यह शिक्षा नीति संपादित करती है, जो आज जन शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस पद्धति में वरिष्ठ विद्यार्थी कनिष्ठ विद्यार्थी को पढ़ाता है। लेखक का मानना है कि यदि सबको शिक्षा देनी है तो इस परंपरागत विधि के मॉडल को हमें दुनिया के सामने लाना होगा, इस मॉडल को भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* पोषित करती है। लेखक का मानना है कि आज पूरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा शास्त्रियों के सामने जो समस्याएँ हैं, उसका उत्तर परंपरागत ज्ञान परंपरा में है, जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा भी कहते हैं।

अध्याय 9 में लेखक भारतीय चिंतन परंपरा के आलोक में अधिगम, पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्र की व्याख्या करते हैं। इसमें लेखक1857 में ब्रिटिश प्रारूप के विश्वविद्यालय बनने के साथ ही भारतीय संस्कृति, विचार और मूल्य स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय चिंतकों के प्रयासों को रेखांकित करते हैं। जिसमें वे भारतेंदु हरिश्चद्र और मदन मोहन मालवीय के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इस परिकल्पना को स्वीकार करने के लिए मदन मोहन मालवीय ने 1904 में आचार्य स्पेक्टस फॉर बनारस हिंदू

यूनिवर्सिटी का प्रकाशन करते हुए, इसमें भारतीय संस्कृति, विचार और मूल्य स्थापित किए। लेखक का मानना है कि इस नीति में पहली बार भारतीय संस्कृति के समृद्ध ज्ञान भंडार की चर्चा की गई है और उसे औपचारिक शिक्षा में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेखक नीति में चर्चित दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों—शोध केंद्रित विश्वविद्यालय और अध्ययन केंद्रित विश्वविद्यालय का उदाहरण लेते हुए यह रेखांकित करते हैं कि यह नीति हमें विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में सहायक होगी।

अगले तीन अध्यायों में भारत की बहुभाषिकता को हमारी संभावनाओं के रूप में विश्लेषित किया गया है। इसके लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा हेतु उल्लिखित विभिन्न संस्तुतियों का समर्थन लिया गया है।

अध्याय 10 '*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*' और हिंदी में लेखक ने यह बताया कि भारत में हिंदी का जो विस्तार हुआ है, उसमें शिक्षा की तुलना में बाजार, सिनेमा, रेल, संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु हिंदी के विस्तार में श्रेष्ठ कहे जाने वाले शिक्षण संस्थानों का कोई विशेष योगदान नहीं है। इसके उन्होंने दो कारण बताए हैं— पहला, त्रिभाषा सूत्र की एक व्याख्या की गई थी कि इसमें अंग्रेजी अपरिहार्य है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर जिन राज्यों में अंग्रेजी नहीं थी वहाँ की उच्चतर माध्यमिक या पूर्व माध्यमिक या कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकृत किया गया और दूसरा प्रभाव सूचना क्रांति का था। उन्होंने बताया कि 1990 के बाद से इंटरनेट के उदय के कारण गूगल सभी प्रश्नों के समाधान और जिज्ञासाओं के केंद्र में आ गया। इसके कारण भाषा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा।

'स्थानीय भाषाएँ— लोक जीवन की प्रतिनिधि' से जुड़ा अध्याय 11 में लेखक ने स्थानीय भाषाओं को धरोहर के रूप में देखने के हमारे दृष्टिकोण की आलोचना की है। लेखक का मानना है कि यदि भाषाओं को धरोहर के रूप में देखा जाएगा तो वे भाषाएँ प्रयोजनमूलक होने के बजाय सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की प्रतीक बनकर रह जाएँगी। इस संदर्भ में वे 'अवेस्ता भाषा' का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि, अवेस्ता एक धार्मिक ग्रंथ की भाषा है। यह पवित्रता के नाम पर जीवित है, परंतु व्यवहार में नहीं है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भाषाओं को धरोहर बनाने के स्थान पर उन्हें जीवन का अंग बनाना चाहती है।

अध्याय 12 'विधि शिक्षा और मातृभाषा' के अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने विधि शिक्षा में भाषा के अंतर्द्वंद्व और भाषागत असंगतता की आलोचना की है एवं उसके कारण शिक्षा के अवसरों में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को रेखांकित करते हुए, इसके समाधान का सुझाव प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि शिक्षा में अवसर की समानता हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को विविध प्रकार की शिक्षा में उसकी भाषा में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। आचार्य शुक्ल का मानना है कि प्रवेश में भाषाई बाधा और न्यायालयों में भाषा का श्रेणीकरण संविधान की मूल भावना 'अवसर की समानता' के विरुद्ध है और यह न्यायसंगत नहीं है।

संवैधानिक मूल्यों पर विचार करते हुए अध्याय 13 'समावेशन द्वारा न्याय और अवसर की समानता' में आचार्य शुक्ल *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में उद्घाटित श्रेष्ठ भारत की निर्मिति के लिए समावेशी शिक्षा द्वारा न्याय और अवसर की समानता के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए समावेशी शिक्षा के लिए नई विद्यालय संस्कृति के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हैं।

'समाज विज्ञान और मानविकी की भारतीय दृष्टि' नामक अध्याय 14 में समाज विज्ञान के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता का प्रतिपादन किया गया है। इस अध्याय में आचार्य शुक्ल ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में विश्लेषित किया है कि समाज विज्ञान सहित भारत की कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक विधाओं आदि को भी भारतीय दृष्टिकोण से न देखकर यूरोसेंट्रिक मॉडल को स्वीकार किया गया है, यह मॉडल मनुष्य को एक यांत्रिक उत्पादक व्यक्ति बनाकर उसकी क्षमताओं का मशीन की क्षमताओं की तरह उपयोग करने की भूमिका में देखता है। जबकि हमें समाज विज्ञान द्वारा समाज और उसके घटकों को समझना है, समाज की निर्मिति के आधारों को समझना है। इसका विकल्प प्रस्तुत करते हुए लेखक बताते हैं कि इसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके भारतीय विद्वत समाज एवं उच्च शिक्षा में लगी मेधाओं को आगे आने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्रियान्वयन के सूत्र से जुड़े अध्याय 15 के अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने भाषा, मानविकी और समाज विज्ञान के ज्ञानानुशासनों को केंद्र में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के क्रियात्मक सूत्रों को प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ-साथ सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन के विद्या स्थानों को भारत केंद्रित दृष्टि के अनुरूप तैयार करने पर बल दिया है। वहीं अध्याय 16 'शिक्षा दर्शन हेतु दर्शन शिक्षा' में आचार्य शुक्ल ने भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपराओं को केंद्र में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार दर्शन के अर्थ को स्पष्ट किया है। इसके अंतर्गत लेखक ने दार्शनिक चिंतन द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया एवं उसके घटकों से संबंधित तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसीय प्रश्नों को खड़ा करने और उनके उत्तरों को खोजने पर बल दिया है। उनके अनुसार *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* पर आधारित मनुष्य निर्माण के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारत की दार्शनिक परंपरा और भारत केंद्रित दृष्टिकोण को शिक्षण प्रक्रिया और विषय-वस्तु के साथ संबंधित करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत आचार्य शुक्ल *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार संस्कृत और दर्शनशास्त्र को विश्वविद्यालयों में अंतर-अनुशासनिक विषय के रूप में स्थापित करने का सुझाव देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि ऐसा होने पर हमारे विद्यास्थान दार्शनिक दृष्टि से संपन्न होंगे।

शिक्षक-विद्यार्थियों की भूमिका पर आधारित अध्याय 17 के अंतर्गत आचार्य शुक्ल परिकल्पित परिवर्तन को धरातल पर उतारने वाले कर्ता के रूप

में शिक्षक की पहचान करते हैं। वे बताते हैं कि शिक्षकों का मूल दायित्व श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करना है। लेखक भारतीय समाज में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए भारतीय गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हैं, जिसमें शिक्षक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, लेखक पुष्ट करते हैं कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* शिक्षक को पुनः शिक्षा के केंद्र में प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य रखती है और शिक्षक को मनुष्य निर्माता की भूमिका के रूप में देखती है।

यह पुस्तक भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक धरोहर का संदर्भ लेते हुए उसकी वर्तमान चुनौतियों की पहचान करती है और *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को आधार बनाते हुए उक्त चुनौतियों के समाधान की संभावनाओं पर चर्चा करती है। यह पुस्तक भारतीय शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए क्रियात्मक सूत्र भी बताती है। पुस्तक की भाषा पठनीय, सरल, बोधगम्य और प्रवाहमय है। यह पुस्तक आरंभ से अंत तक पाठक को बाँधे रखती है। इस पुस्तक में लेखक की सूक्तिपरक शैली और सरल हिंदी भी अवलोकनीय है। निश्चित रूप से यह पुस्तक *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का एक सांगोपांग भाष्य है, जो पाठक को भारतीय शिक्षा को समझने में सहायक होगी।